



## मदरसों की शिक्षा

### चर्चा में क्यों

हाल ही में, [राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग \(NCPDR\)](#) ने [शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009](#) के गैर-अनुपालन का हवाला देते हुए भारत में मदरसा शिक्षा के बारे में चर्चा व्यक्त की।

### प्रमुख बिंदु

- **NCPDR की चर्चाएँ:** NCPDR ने [सर्वोच्च न्यायालय](#) को सूचित किया कि मदरसा शिक्षा व्यापक नहीं है और यह [शिक्षा का अधिकार अधिनियम \(RTE\), 2009](#) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती है।
- मदरसों में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकें कथित तौर पर '[इस्लाम की सर्वोच्चता](#)' को बढ़ावा देती हैं, जो [धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक सिद्धांतों](#) और [RTE आवश्यकताओं](#) के विपरीत है।
- **उच्च न्यायालय का नरिणय:** इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने [उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004](#) को 'असंवैधानिक' घोषित किया।
  - यह अधिनियम '[धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत](#)' तथा [संवैधानिक अनुच्छेद 14](#) के तहत [मौलिक अधिकारों का उल्लंघन](#) करता पाया गया।
- **मदरसा:** मदरसा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ शैक्षणिक संस्थान होता है।
  - आरंभ में, इस्लाम में [मस्जिदें](#) शैक्षणिक संस्थानों के रूप में संचालित होती थीं, लेकिन 10 वीं शताब्दी तक, मदरसे इस्लामी दुनिया में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दोनों के लिये अलग-अलग संस्थाओं के रूप में विकसित हो गए।
  - सबसे प्रारंभिक मदरसे [खुरासान और ट्रांसोक्सेनिया](#) (आधुनिक पूर्वी व उत्तरी ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान) में पाए गए, जहाँ बड़े संस्थान छात्रों, विशेष रूप से गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों के लिये आवास उपलब्ध कराते थे।
  - **सत्र 2018-19** तक, भारत में **24,010 मदरसे थे: 19,132 मान्यता प्राप्त और 4,878 गैर-मान्यता प्राप्त।**
  - मान्यता प्राप्त मदरसे [राज्य बोर्ड के अधीन](#) हैं; गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे [दारुल उलूम नदवतुल उलमा](#) और [दारुल उलूम देवबंद](#) जैसे प्रमुख मदरसों के पाठ्यक्रम का पालन करते हैं।
- देश के **60% मदरसे उत्तर प्रदेश में** हैं। जिनमें **11,621 मान्यता प्राप्त और 2,907 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे** हैं।
- **भारत में मदरसों की श्रेणियाँ**
- **मदरसा दरसे नज़ामी:** सार्वजनिक दान के रूप में संचालित होते हैं और इन्हें राज्य स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम का पालन करना आवश्यक नहीं है
  - **मदरसा दरसे आलिया:** राज्य मदरसा शिक्षा बोर्डों से संबद्ध (जैसे, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड)।
- राज्य सरकारों द्वारा शासित, शिक्षकों और अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।
- वर्ष 2023 में लगभग **1.69 लाख छात्र** उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड परीक्षा (कक्षा 10 और कक्षा 12 के समकक्ष) में उपस्थित हुए।
- **मदरसों के लिये वित्तपोषण:** वित्तपोषण का बड़ा हिस्सा संबंधित राज्य सरकारों से आता है।
- **केंद्र सरकार की योजना:** [मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना \(SPEMM\)](#) मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **SPEMM के अंतर्गत उप-योजनाएँ:**
  - मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPQEM)
  - अल्पसंख्यक संस्थानों का अवसरचना विकास (IDMI)
- अप्रैल 2021 में SPEMM को [अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय](#) से [शिक्षा मंत्रालय](#) में स्थानांतरित कर दिया गया।

## राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

- NCPDR एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना मार्च 2007 में [बाल अधिकार संरक्षण आयोग \(CPCR\) अधिनियम, 2005](#) के तहत की गई थी।
- यह [महिला एवं बाल विकास मंत्रालय](#) के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान एवं बाल अधिकारों पर [संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में नहित बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य](#) के अनुरूप हों।
- यह [शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009](#) के अंतर्गत बच्चों के नशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है।

- यह [लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 \(POCSO\)](https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/madrasa-education-1) के कार्यान्वयन की नगिरानी करता है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/madrasa-education-1>

